झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विधिक याचिका संख्या 4361/2022

मेसर्स सुंदर ट्रांसपोर्ट, एक साझेदारी फर्म जिसका प्रतिनिधित्व श्रीमती किरण देवी उम्र लगभग 50 वर्ष, पति राज किशोर सिंह के माध्यम से, दोनों का कार्यालय दूकान संख्या 26, रोड संख्या 08, टेल्को कॉलोनी, डाकघर और थाना टेल्को, जमशेदपुर, जिला पूर्व सिंहभूम

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. विजय सिंह, पिता स्व. सीतल सिंह, निवासी हाउस नंबर 9 क्रॉस रोड नंबर 2, प्रकाश नगर, रिवर व्यू कॉलोनी, टेल्को, डाकघर और थाना टेल्को, शहर जमशेदपुर, जिला सिंहभूम पूर्व, पिन कोड संख्या 831004 झारखंड

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री पी.ए.एस. पति, अधिवक्ता
राज्य के लिए: सुश्री कुमारी रश्मि, अतिरिक्त लोक अभियोजक
विरोधी संख्या 2 के लिए: सुश्री लक्ष्मी पांडे, अधिवक्ता

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ 01.09.2022 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो आपराधिक पुनरावलोकन संख्या 59/2022 में है। इसके तहत, माननीय सत्र न्यायाधीश, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर ने शिकायत मामला संख्या 395/2016 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष भेजा है और निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता को इस आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्ता, अर्थात् एम/एस सुंदर ट्रांसपोर्ट को उक्त शिकायत मामले के शीर्षक में आरोपी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाए, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, सह-आरोपी सुनील एम. बाफना ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सात चेक जारी किए, जो अस्वीकृत हो गए। वर्तमान शिकायत मामला संख्या 395/2016 तीन चेकों के अस्वीकृत होने से संबंधित है, अर्थात् पहला चेक संख्या 393487 दिनांक 02.12.2015 को ₹10,00,000/- का, दूसरा चेक संख्या 393486 दिनांक 03.12.2015 को ₹19,00,000/- का और तीसरा चेक संख्या 393485 दिनांक 04.12.2015 को ₹19,00,000/- का है। सभी तीन चेकों को शिकायतकर्ता द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया गया था और इन्हें 'कोष की कमी' के कारण 08.12.2015 को तीन अलग-अलग चेक वापसी मेमो के माध्यम से बैंक द्वारा वापस कर दिया गया। चेकों की राशि की मांग करने वाला नोटिस 02.01.2016 को केवल सह-आरोपी सुनील एम. बाफना को जारी किया गया और याचिकाकर्ता साझेदारी फर्म को नहीं। भारतीय डाक के माध्यम से भेजे गए

उक्त पंजीकृत पत्र की ऑनलाइन डिलीवरी रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजीकृत पत्र 04.01.2016 को केवल सुनील एम. बाफना को वितरित किया गया। शिकायत 10.02.2016 को दायर की गई और माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने अकेले आरोपी सुनील एम. बाफना के खिलाफ धारा 138 के तहत प्राथमिक दृष्टया मामला पाया और समन जारी करने का आदेश दिया। सह-आरोपी सुनील एम. बाफना ने आपराधिक विधिक याचिका संख्या 3055/2017 दायर की, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया कि वह एम/एस सुंदर ट्रांसपोर्ट का भागीदार है और साझेदारी फर्म को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इसके बाद शिकायतकर्ता/इस आपराधिक विविध याचिका का प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत याचिकाकर्ता साझेदारी फर्म को अतिरिक्त रूप से आरोपी के रूप में समन करने के लिए एक आवेदन दायर किया| न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने 04.01.2022 को शिकायत मामला संख्या 395/2016 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत दायर की गई याचिका को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि एम/एस सुंदर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभिक चरण में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था और इस आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्ता को देर से आरोपी बनाना धारा 138 के प्रावधानों के विपरीत होगा। याचिकाकर्ता ने जमशेदपुर में पूर्व सिंहभूम के सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक पुनरावलोकन संख्या 59/2022 दायर की। माननीय सत्र न्यायाधीश, पूर्व सिंहभूम ने 01.09.2022 को आपराधिक पुनरावलोकन संख्या 59/2022 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बिलकचंद ग्यानचंद कंपनी बनाम ए. ए. चिन्नास्वामी** मामले जिसे **(1999) 5 एससीसी 693** में रिपोर्ट किया गया है, में दिए गए निर्णय पर निर्भर किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनी के निदेशक को जारी किया गया मांग नोटिस कंपनी पर भी पर्याप्त नोटिस है। सत्र न्यायाधीश ने यह ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपी सुनील एम. बाफना ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एम/एस सुंदर ट्रांसपोर्ट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में प्रश्नांकित चेक जारी किए थे, यह देखा कि सह-आरोपी सुनील एम. बाफना को दिया गया नोटिस फर्म के लिए नोटिस के समान है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा 04.01.2022 को पारित आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने मामले को संबंधित अदालत में वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को एम/एस सुंदर ट्रांसपोर्ट को आरोपी के रूप में नामित करने की अनुमति दी जाए।

4. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **एन. हरिहर कृष्णन बनाम जे. थॉमस**, **(2018) 13 एससीसी 663** मामले के निर्णय पर निर्भर करते हैं,जिसके पैराग्राफ 27, 28 और 29 इस प्रकार हैं:

> *27. इस अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति के अनुसार, अपराध की पहली विशेषता यह है कि किसी व्यक्ति ने एक चेक जारी किया। चेक के जारीकर्ता की पहचान शिकायतकर्ता (भुगतानकर्ता) को ज्ञात होना आवश्यक है और इसकी जांच की आवश्यकता होती है, और सामान्यतः यह विवाद में नहीं होता जब तक कि जिस व्यक्ति पर चेक जारी करने का आरोप है, वह उस तथ्य का विवाद न करे। चेक को अंततः अस्वीकृत किए जाने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए आवश्यक अन्य तथ्य यह साबित करना है कि चेक का भुगतान करने वाले ने अभियोजन शुरू करने से पहले अधिनियम की धारा 138 के तहत विचारित प्रत्येक चरण का पालन किया। क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पहले ही यह कहा जा चुका है कि धारा 138 के तहत विचारित किसी भी एक चरण का पालन न करना*

"अभियोजन के लिए कारण" प्रदान नहीं करेगा। इसलिए, धारा 138 के तहत अभियोजन के संदर्भ में, अपराध का संज्ञान लेना लेकिन अपराधी का नहीं होना उपयुक्त नहीं है। जब तक शिकायत में अपराध की प्रत्येक विशेषता को स्थापित करने वाले सभी आवश्यक तथ्यों का उल्लेख नहीं होता, तब तक न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। चेक जारी करने वाले व्यक्ति का नाम प्रकट करना उन तथ्यों में से एक है जो शिकायत में होना आवश्यक है। अन्यथा, यदि धारा 138 के तहत अपराध की जांच करने के लिए कोई विधिक अधिकार नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके खिलाफ न्यायालय कार्यवाही कर सके। बिना आरोपी के अभियोजन नहीं हो सकता। धारा 138 के तहत अपराध व्यक्ति विशेष होता है। इसलिए, संसद ने धारा 142 के तहत घोषित किया कि संज्ञान लेने से संबंधित प्रावधानों को दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई प्रक्रियाओं को छोड देना चाहिए। इसलिए धारा 142 के तहत गैर-प्रतिबंधात्मक खंड का उद्घाटन भी किया गया। यह भी याद रखना चाहिए कि धारा 142 न तो पुलिस को रिपोर्ट करने की कल्पना करती है और न ही न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए पुलिस को शिकायत की जांच करने का निर्देश देती है।

28. यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादी के पास अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के भीतर दक्षिण के खिलाफ शिकायत न दायर करने का पर्याप्त कारण था, नीचे के किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं जांचा गया है। जैसा कि सही ढंग से इंगित किया गया है, यह आवेदन, जो वर्तमान अपील का विषय है और जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का उपयोग करते हुए दायर किया गया है, केवल एक साधन है जिसके द्वारा प्रतिवादी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के पार दक्षिण के खिलाफ अभियोजन शुरू करने का प्रयास कर रहा है।

29. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 142 न्यायालय को उचित मामलों में देरी को माफ करने की अनुमति देती है। हमें देरी को माफ करने का कोई कारण नहीं मिलता। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क कि परीक्षण के दौरान प्रतिवादी को यह एहसास हुआ कि प्रश्नांकित चेक दक्षिण के खाते पर जारी किया गया था, स्पष्ट रूप से एक झूठा बयान है। चेक के सामने यह स्पष्ट है कि यह दक्षिण के खाते पर जारी किया गया था। निस्संदेह, प्रतिवादी ने दक्षिण को धारा 138 के उपधारा (b) के प्रावधान के तहत नोटिस जारी किया। यह तथ्य उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है। संबंधित भाग पहले ही पैराग्राफ 15 में निकाला जा चुका है।" (जोर दिया गया)

और यह प्रस्तुत करता है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि धारा 138 के तहत अभियोजन के संदर्भ में अपराध का संज्ञान लेना लेकिन अपराधी का नहीं होना उपयुक्त नहीं है। धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए अन्य मामलों की तुलना में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय की अधिकारिता को अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के पार नहीं लाया जा सकता। इस मामले में, न तो देरी को माफ

करने के लिए कोई प्रार्थना की गई और न ही कोई देरी माफ की गई, और न ही याचिकाकर्ता को कोई मांग नोटिस कभी जारी किया गया, जो कि धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित मामले में किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में नामित करने के लिए आवश्यक है।

5. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विवादित रूप से "सुंदर ट्रांसपोर्ट के लिए" शब्द सुनील एम. बाफना द्वारा जारी किए गए चेक पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था और शिकायत में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि चेक सुंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जारी किया गया था; इसलिए, माननीय सत्र न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को एम/एस सुंदर ट्रांसपोर्ट को आरोपी के रूप में नामित करने का निर्देश देकर एक गंभीर गलती की है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित करने का आदेश देकर कानून के स्थापित सिद्धांत को नजरअंदाज करते हुए एक गंभीर गलती की है।

6. इस संबंध में, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता इस न्यायालय के **एम/एस सुंदर ट्रांसपोर्ट बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य**, जो कि क्रिमिनल विविध याचिका संख्या 4320/2022 में 4 दिसंबर, 2023 को पारित किया गया था के निर्णय पर निर्भर करते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह कहा कि धारा 319(4)(बी) के तहत विचारित प्रावधान नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन पर लागू नहीं होंगे।

7. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के **हिमांशु बनाम बी. शिवमूर्ति और अन्य** के मामले में है, जो **(2019) 3 एससीसी 797** में रिपोर्ट किया गया है के निर्णय पर निर्भर करते हैं, जिसकी पैराग्राफ 13 इस प्रकार है:

कंपनी को आरोपी के रूप में नामित किए बिना, अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत इसलिए कायम नहीं की जा सकती थी। अपीलकर्ता ने चेक पर कंपनी के निदेशक के रूप में और उसकी ओर से हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, कंपनी पर मांग का नोटिस भेजे बिना और धारा 138 के उपबंध का पालन किए बिना, उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की कि कंपनी को अब आरोपी के रूप में नामित किया जा सकता है।" (विशेष बल दिया गया)

और यह प्रस्तुत करता है कि साझेदारी फर्म पर मांग का नोटिस भेजे बिना और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के उपबंध का पालन किए बिना, वर्तमान आपराधिक विधिक याचिका का याचिकाकर्ता आरोपी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर, 01.09.2022 को माननीय सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश, जिसके तहत माननीय सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को इस आपराधिक विधिक याचिका के याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित करने की अनुमति दें, कानूनी रूप से स्थायी नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि समस्त आपराधिक कार्यवाही और 01.09.2022 को पारित आदेश, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 59/2022 को रद्द और निरस्त किया जाए।

8. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक और विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए उपस्थित वकील, दूसरी ओर, समस्त आपराधिक कार्यवाही और 01.09.2022 को पारित आदेश, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 59/2022 को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध करते हैं। विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता, जो एक साझेदारी फर्म है, को धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में नामित करने का निर्देश दिया गया है। विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (4) (बी) की ओर आकर्षित करते हैं, जो इस प्रकार है:

319. अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति जो अपराध के लिए दोषी प्रतीत

होते हैं-

1. xxxxxx
2. xxxxxx
3. xxxxxx
4. जहाँ न्यायालय उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है, तब-

(a) xxxxx;

(b) जैसे कि ऐसा व्यक्ति आरोपी व्यक्ति रहा हो जब न्यायालय ने उस अपराध की संज्ञान लिया जिस पर जांच या परीक्षण प्रारंभ किया गया था।

विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मामला ऐसे ही आगे बढ़ सकता है जैसे कि वह आरोपी व्यक्ति रहा हो जब न्यायालय ने उस अपराध की संज्ञान लिया जिस पर जांच या परीक्षण प्रारंभ किया गया था। इसके बाद विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि शुरुआत में शिकायतकर्ता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि मेसर्स सुंदर ट्रांसपोर्ट एक साझेदारी फर्म है, इसलिए उसने इसे शिकायत में आरोपी के रूप में नामित करना या उस पर मांग का नोटिस भेजना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि 01.09.2022 को पारित आदेश, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 59/2022 में कोई अवैधता नहीं होने के कारण, यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज की जाए।

9. बार में की गई प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **एन. हरिहर कृष्णन बनाम जे.थॉमस** (उपरोक्त) मामले में कहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन के संदर्भ में, अपराध की संज्ञान लेने की अवधारणा लेकिन अपराधी की नहीं होना उचित नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन के संदर्भ में, अपराध की संज्ञान अपराधी के खिलाफ भी ली जानी चाहिए और प्रत्येक ऐसे अपराधी को मांग का नोटिस दिया जाना चाहिए जैसा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के उपबंध में परिकल्पित किया गया है और जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **हिमांशु बनाम बी. शिवमूर्ति और अन्य** मामले (उपरोक्त) में कहा है।

10. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को कभी भी मांग का नोटिस नहीं भेजा गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (बी) में परिकल्पित की गई मान्य प्रावधान नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अभियोजन पर लागू नहीं होती; भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एन. हरिहर कृष्णन बनाम जे. थॉमस (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के भाग के दृष्टिगत, जिसका प्रासंगिक भाग पहले इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैरा में उद्धृत किया जा चुका है। निर्विवाद रूप से, उस समय अवधि का अंत हो चुका है जिसके भीतर याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध की संज्ञान ली जा सकती थी और न तो देरी को माफ करने की कोई प्रार्थना की गई है और न ही सत्र न्यायाधीश ने इस पहलू पर विचार किया है जब उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित करने का निर्देश दिया।

11. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि माननीय सत्र न्यायाधीश, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर ने मामले में याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में शामिल करने का निर्देश देकर एक गंभीर अवैधता और गंभीर त्रुटि की है। इसलिए, 01.09.2022 को पारित आदेश, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 59/2022, जिसके तहत माननीय सत्र न्यायाधीश, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर ने शिकायत मामले संख्या 395/2016 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के न्यायालय में वापस भेजने का निर्देश दिया है ताकि शिकायतकर्ता को इस

आपराधिक विधिक याचिका के याचिकाकर्ता, अर्थात् मेसर्स सुंदर ट्रांसपोर्ट, जो एक साझेदारी फर्म है, को अभियुक्त के रूप में नामित करने की अनुमति दी जा सके, कानूनी रूप से स्थायी नहीं है और इसलिए इसे रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए।

12. इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार, समस्त आपराधिक कार्यवाही और 01.09.2022 को पारित आदेश, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 59/2022, याचिकाकर्ता के खिलाफ रद्द और निरस्त किया जाता है।

13. परिणामस्वरूप, अतः, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

11. वर्तमान आपराधिक विधिक याचिका के निपटारे के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता को 20.12.2022 के आदेश द्वारा प्रदान की गई अंतरिम राहत रद्द की जाती है।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 दिसंबर 2023
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|